



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928

No. 1380]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

(आय-कर)

का.आ. 1977(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (42) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए,—

1. (क) पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय, 38-क, गैलियंट, बगमालो रोड, दाबोलिन, गोवा को निकाय के रूप में ;
- (ख) पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को बैंककारी कंपनी के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में उद्भूत होने वाली किसी ऐसी आय को, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, विनिर्दिष्ट आय के रूप में,

अधिसूचित करती है ।

2. यह अधिसूचना, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 338/2006/फा. सं. 149/186/2005-टीपीएल]

वन्दना रामचन्द्रन, अवर सचिव (टीपीएल-1)

स्पष्टीकारक ज्ञापन :

एक निकाय के रूप में, पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को, और किसी बैंककारी कंपनी के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में, उक्त सचिवालय को उद्भूत होने वाली किसी आय को, जिसको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (42) के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आय के रूप में,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, अधिसूचित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित अधिसूचना, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी।

धारा 10 का खंड (42), जो वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा, 1 अप्रैल, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से, अंतःस्थापित किया गया था, उपबंधित करता है कि दो या अधिक देशों से, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी संधि या करार या केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किसी अभिसमय के अधीन, स्थापित या गठित या नियुक्त किए गए किसी अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण, और जिसको लाभ के प्रयोजन के लिए स्थापित या गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, को उद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, ऐसे निकाय या प्राधिकरण की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी।

पुनर् राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को बैंक ब्याज के रूप में उद्भूत होने वाली किसी आय का, जो वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अन्यथा कर योग्य होती, आय कर से छूट प्राप्त होना प्रस्तावित की जाती है। अतः, वर्तमान अधिसूचना को, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने योग्य बनाने के लिए, प्रस्तावित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से, इस अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th November, 2006
(INCOME-TAX)

S.O. 1977(E).— In exercise of the powers conferred by clause (42) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, -

1. (a) the Secretariat of Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control, 38-A, Galliant, Bogmalo Road, Dabolim, Goa as the body;
- (b) any income arising to the Secretariat of Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control, by way of interest on deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies, as the specified income,

for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be applicable for assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

Explanatory Memorandum:

It is proposed to notify the Secretariat of Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control as the body and any income arising to the said Secretariat by way of interest on deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies as the specified income for the purposes of clause (42) of section 10 of the Income-tax Act, 1961. The proposed notification shall be applicable for assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

Clause (42) of section 10, which was inserted, vide the Finance Act, 2006 with retrospective effect from the 1st day of April, 2006, provides that any specified income arising to a notified body or authority established or constituted or appointed under a treaty or an agreement entered into by the Central Government with two or more countries or a convention signed by the Central Government and is established or constituted or appointed not for the purpose of profit shall not be included in the total income of such body or authority.

Any income arising by way of bank interest to the Secretariat of Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control which would otherwise be taxable for the financial year 2005-06 is proposed to be exempted from income-tax. The present notification is therefore proposed to be made applicable retrospectively for assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

It is certified that no assessee is likely to be prejudicially affected by this notification being given retrospective effect.